



Neutral Citation No- 2026: AHC:174085

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 95/2026

तारिक वसीम @ तारीक वसीम

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अखिलेश कुमार तिवारी, रोहित कुमार चतुर्वेदी

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : अनिल कुमार त्रिपाठी, शासकीय अधिवक्ता, गोपाल द्विवेदी, शशि शंकर त्रिपाठी, उत्सव

न्यायालय संख्या - 86

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद कुमार श्रीवास्तव, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री उत्सव, और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह आवेदन दायर किया है, जिसका उल्लेख आवेदन के प्रार्थना खंड में किया गया है। आवेदन में जिस राहत का उल्लेख किया गया है, वह नीचे दी गई है: -

"इसलिए, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय इस आवेदन को स्वीकृति देने और सब वाद संख्या 80/2024 (राज्य बनाम सब्बीर अहमद @ पप्पू और अन्य) में शुरू की गई संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने/रद्द करने की कृपा करे, भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 343, 365, 365, 395, 419, 420, 467, 468, 471, 506, 34 और 412 के तहत, जो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2023 के वाद अपराध संख्या 117 से उत्पन्न हुई है, भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 343, 365, 395, 419, 420, 467, 468, 471, 506 और 34 के तहत, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर II, जौनपुर के समक्ष लंबित है।

और/या ऐसा अन्य और आगे का आदेश पारित करना जिसे यह माननीय न्यायालय इस वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में ठीक और उचित समझे।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि विपक्षी संख्या 2 ने इस आवेदक सहित छह आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ 01.06.2023 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 2023 की धारा 342, 343, 365, 395, 419, 420, 467, 468, 471, 506, 34 भारतीय दंड संहिता, पुलिस थाना मछली शहर, जिला-जौनपुर के तहत 2023 के वाद अपराध संख्या 117 के रूप में दर्ज की गई थी और जांच के बाद 27.11.2023 को धारा 342, 343, 365, 395, 419, 420, 467, 468, 471, 506, 34, 412 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। इसके बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संज्ञान-सह-सम्मन आदेश पारित किया और उसके बाद, वाद को सत्र न्यायालय में सौंप दिया लेकिन अभी तक आरोप तय नहीं किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने आरोप पत्र के साथ-साथ संज्ञान-सह-समन आदेश को चुनौती नहीं दी है, बल्कि उन्होंने इस आवेदन में आपराधिक वाद की संपूर्ण कार्यवाही को चुनौती दी है, जो सत्र न्यायाधीश के समक्ष लंबित है और फिर भी उसमें आरोप तय किया जाना है। उन्होंने आगे कहा है कि इस आवेदक के खिलाफ आरोप विपक्षी संख्या 2 की मां की जाली पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करने का है। उन्होंने आगे कहा है कि आवेदक निर्दोष है, उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित रूप से कोई अपराध नहीं किया है और उसे किसी गुप्त उद्देश्य के कारण इस वाद में फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि पक्षों के बीच विवाद विशुद्ध रूप से नागरिक प्रकृति का है और इसके लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष एक सिविल मुकदमा पहले से ही लंबित है। उन्होंने आगे कहा है कि विपक्षी संख्या 2 ने आवेदक को परेशान करने के लिए नागरिक प्रकृति से संबंधित वाद को आपराधिक रंग देने की कोशिश की है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आरोप पत्र के आधार पर संज्ञान लिया गया है और यह कानून के अनुसार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि विचारण न्यायालय ने संज्ञान आदेश पारित करते समय जांच अधिकारी द्वारा एकत्र की गई पूरी सामग्री को उसके सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा और उसका विश्लेषण नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक के खिलाफ किसी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भी अपराध का खुलासा नहीं किया गया है और विचारण न्यायालय इस बात पर विचार करने में पूरी तरह से विफल रहा है कि आवेदक के खिलाफ जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, उन्होंने कहा है कि आपराधिक वाद की पूरी कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है/रद्द किया जा सकता है। अंत में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यदि इस न्यायालय को इस आवेदन में योग्यता नहीं मिलती है, तो वैकल्पिक रूप से संबंधित विचारण न्यायालय को धारा 227 आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संबंधित धारा 250 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अनुसार आरोप तय करते समय अभियुक्त/आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए एक उचित निर्देश जारी किया जा सकता है।

5. इसके विपरीत, विद्वान राज्य के अधिवक्ता ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को संक्षिप्त विचारण करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में, उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अखिल शारदा और अन्य, (2023) 11 उच्चतम न्यायालय के पवाद 626, केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम आर्यन सिंह और अन्य, (2023) 18 उच्चतम न्यायालय के वाद 399 और नरेश अनेजा उर्फ नरेश कुमार अनेजा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2025) 2 उच्चतम न्यायालय के वाद 604 में पारित निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है।

6. विद्वान राज्य के अधिवक्ता ने आगे कहा कि जांच के दौरान विवेचना अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सामग्री को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के तहत साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है, जब तक कि गवाहों की शपथ के साथ-साथ जिरह पर मुख्य परीक्षा में जांच नहीं की जाती है और जो दस्तावेज प्रदान किए गए हैं, वे भी वाद के मुकदमे के दौरान गवाहों द्वारा साबित किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि आक्षेपित संज्ञान-सह-समन आदेश में कोई अनियमितता नहीं है, जो धारा 507 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (संबंधित धारा 461 दंड प्रक्रिया संहिता) के प्रावधानों के अनुसार आपराधिक कार्यवाही को दूषित कर सकता है। धारा 507 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों को तैयार संदर्भ के लिए नीचे चित्रित किया गया है: -

"धारा 507 - अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती हैं- यदि कोई मजिस्ट्रेट, इस संबंध में कानून द्वारा सशक्त नहीं होने के कारण, निम्नलिखित में से कोई भी काम करता है, अर्थात्:

(क) धारा 85 के तहत संपत्ति कुर्क और बेचता है;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ख) एक डाक प्राधिकारी की हिरासत में एक दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीजों के लिए एक खोज-वारंट जारी करता है;

(ग) शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा की मांग करता है;

(घ) अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा की मांग करता है;

(ङ) एक व्यक्ति को कानूनी रूप से अच्छे व्यवहार के लिए बाध्य करता है;

(च) शांति बनाए रखने के लिए एक बांड रद्द करता है;

(छ) रखरखाव के लिए एक आदेश देता है;

(ज) एक स्थानीय उपद्रव के रूप में धारा 152 के तहत एक आदेश बनाता है;

(झ) धारा 162 के तहत, एक सार्वजनिक उपद्रव की पुनरावृत्ति या निरंतरता को प्रतिबंधित करता है;

(ञ) अध्याय XI के भाग सी या भाग डी के तहत एक आदेश बनाता है;

(ट) धारा 210 की उपधारा (1) के खंड (सी) के तहत एक अपराध का संज्ञान लेता है;

(ठ) एक अपराधी की कोशिश करता है;

(ड) एक अपराधी को सरसरी तौर पर कोशिश करता है;

(ढ) धारा 364 के तहत, किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई कार्यवाही पर एक वाक्य पारित करता है;

(ण) एक अपील का निर्णय लेता है;

(त) कार्यवाही के लिए धारा 438 के तहत कॉल करता है; या

(थ) धारा 491 के तहत पारित आदेश को संशोधित करता है, उसकी कार्यवाही शून्य होगी।

7. विद्वान राज्य के अधिवक्ता ने आगे कहा कि यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि **प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना का विश्वकोश नहीं है** और इसमें घटना के हर पहलू का पूर्ण, कालानुक्रमिक विवरण शामिल होने की उम्मीद नहीं है, बल्कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य पुलिस को एक संज्ञेय अपराध (एक गंभीर अपराध जहां पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है) के कमीशन के बारे में सूचित करना है ताकि वे जांच शुरू कर सकें। अपने तर्क को पुष्ट करने के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लिए, उन्होंने वी.के. मिश्रा और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, (2015) 9 उच्चतम न्यायालय के वाद 588, लतेश उर्फ दादू बाबूराव कार्लेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2018) 3 उच्चतम न्यायालय के पवाद 66, अमीश देवगन बनाम भारत संघ और अन्य, (2021) 1 एससीसी 1 के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर भरोसा किया है।

8. विद्वान राज्य के अधिवक्ता आगे कहते हैं कि हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बी.एन. जॉन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, [2025] 1 एससीआर 12: 2025 आईएनएससी 4 के वाद के पैराग्राफ 25 में कानून के उपरोक्त प्रस्ताव को दोहराया है जैसा कि उसके पहले के निर्णयों में प्रतिपादित किया गया है। बी.एन. जॉन के वाद (उपरोक्त) के प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 25 को तैयार संदर्भ के लिए नीचे दर्शाया गया है: -

"25. प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलकर्ता द्वारा आपराधिक बल के उपयोग या हमले का कोई आरोप नहीं है ताकि भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के प्रावधान को लागू किया जा सके। यह याद रखना चाहिए कि एक आपराधिक प्रक्रिया केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के साथ शुरू की जाती है। हालांकि प्रथम सूचना रिपोर्ट को घटना के सभी विस्तृत तथ्यों वाला एक विश्वकोश नहीं माना जाता है और यह केवल एक दस्तावेज है जो आपराधिक कानूनी प्रक्रिया को ट्रिगर करता है और गति देता है, फिर भी इसे कथित रूप से किए गए अपराध की प्रकृति का खुलासा करना चाहिए, अन्यथा यह **भजन लाल के वाद (उपरोक्त)** (निर्णय के पैरा 102 के खंड 1 के अनुसार) में आयोजित किए गए अपराध की प्रकृति का खुलासा करना होगा।

सीबीआई बनाम तपन कुमार सिंह, (2003) 6 एससीसी 175 में इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"20. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक प्रथम सूचना रिपोर्ट एक विश्वकोश नहीं है, जिसमें रिपोर्ट किए गए अपराध से संबंधित सभी तथ्यों और विवरणों का खुलासा करना चाहिए। एक मुखबिर किसी अपराध के कमीशन के बारे में एक रिपोर्ट दर्ज कर सकता है, हालांकि वह पीड़ित या उसके हमलावर का नाम नहीं जानता है। वह यह भी नहीं जानता कि घटना कैसे हुई। एक पहले मुखबिर को आवश्यक रूप से एक चश्मदीद गवाह होने की आवश्यकता नहीं है ताकि वह किए गए अपराध के सभी पहलुओं का विस्तार से खुलासा करने में सक्षम हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि दी गई जानकारी को एक संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा करना चाहिए और इस

तरह दर्ज की गई जानकारी को पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध के कमीशन पर संदेह करने के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लिए एक आधार प्रदान करना चाहिए। इस स्तर पर यह पर्याप्त है यदि पुलिस अधिकारी दी गई जानकारी के आधार पर एक संज्ञेय अपराध के कमीशन पर संदेह करता है, न कि उसे आश्वस्त या संतुष्ट होना चाहिए कि एक संज्ञेय अपराध किया गया है। यदि उसके पास प्राप्त जानकारी के आधार पर संदेह करने के कारण हैं कि संज्ञेय अपराध किया गया है, तो वह जानकारी दर्ज करने और जांच करने के लिए बाध्य है। इस स्तर पर उसके लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वह सूचना की सत्यता के बारे में खुद को संतुष्ट करें.....”

(महत्व प्रदत्त)”

9. विद्वान राज्य अधिवक्ता आगे निवेदित करते हैं कि विद्वान विशेष न्यायालय ने विधि के अनुसार तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गुजरात राज्य बनाम गिरीश राधाकृष्णन वारदे; (2014) 3 एससीसी 659 के प्रकरण में पैराग्राफ संख्या 13 एवं 14 में प्रतिपादित विधि के अनुरूप संज्ञान ग्रहण किया है। पैराग्राफ संख्या 13 एवं 14 को निम्नवत् उद्धृत किया गया है:

“13. लेकिन अगर पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत पुलिस स्टेशन में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया जाता है, न कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (ए) के तहत मजिस्ट्रेट के सामने, तो जाहिर है कि मजिस्ट्रेट जांच उस प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में नहीं की जा सकती है जो दर्ज की गई थी क्योंकि यह पुलिस की जांच एजेंसी है जो कानूनी रूप से जांच करने की हकदार है और उसके बाद, आरोप पत्र प्रस्तुत करता है जब तक कि मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत भी दर्ज नहीं की जाती है, जहां शिकायत के मामलों के लिए निर्धारित प्रक्रिया लागू होगी। हालांकि, एक पुलिस वाद में, आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद, मामला मजिस्ट्रेट के पास एक राय बनाने के लिए जाता है कि क्या यह एक ऐसे वाद में संज्ञान लेने और वाद को मुकदमे के लिए करने के लिए उपयुक्त मामला है जो प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से पुलिस के समक्ष दर्ज किया गया है और मजिस्ट्रेट जांच पूरी होने और पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद आरोपपत्र में किसी भी धारा को बाहर या शामिल नहीं कर सकता है।

14. इसलिए, यह सवाल उठता है कि क्या शिकायतकर्ता/मुखबिर/अभियोजन पक्ष को एक उपाय की तलाश करने से रोका जाएगा यदि जांच अधिकारी भारतीय दंड संहिता की उन सभी धाराओं को शामिल नहीं करके अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं, जिन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रकट तथ्यों के बावजूद अपराध को माना जा सकता है। उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक होना चाहिए क्योंकि अभियोजन पक्ष को उन धाराओं के बहिष्करण की अनदेखी करके पूर्वाग्रह का सामना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो अपराध का गठन करते हैं यदि जांच अधिकारी किसी भी कारण



से प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर सभी अपराधों को आरोपपत्र में शामिल करने में विफल रहे हैं, जिस पर जांच की गई थी। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है कि क्या इस कमी को उस मजिस्ट्रेट द्वारा भरने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके सामने आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद संज्ञान लेने के लिए वाद आता है और जैसा कि पहले ही कहा गया है, एक ऐसे वाद में मजिस्ट्रेट जो पुलिस रिपोर्ट पर आधारित है, संज्ञान लेने के समय धाराओं को जोड़ या घटा नहीं सकता है क्योंकि यह केवल विचारण न्यायालय द्वारा धारा 216, 218 के तहत या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 228 के तहत आरोप तय करने के समय ही अनुमति दी जाएगी, जैसा कि वाद हो, जिसका अर्थ है कि आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद अभियोजन पक्ष के लिए आरोप तय करने के चरण में उचित विचारण न्यायालय के समक्ष बहस करने के लिए खुला होगा ताकि यह स्थापित किया जा सके कि तथ्यों की दी गई स्थिति पर उचित धाराएं जो अभियोजन पक्ष के अनुसार तैयार की जानी चाहिए, को तैयार करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके साथ ही, अभियुक्त को इस स्तर पर यह प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता भी है कि क्या किसी विशेष प्रावधान के तहत आरोप तय किया जाना चाहिए या नहीं और यह पुलिस रिपोर्ट के आधार पर वाद में यह निर्धारित करने के लिए उपयुक्त मंच है कि क्या आरोप तय किया जा सकता है और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर किसी विशेष धारा को जोड़ा या हटाया जा सकता है और प्रथम सूचना रिपोर्ट और चार्जशीट में प्रकट तथ्यों के आधार पर भी।

(जोर दिया गया)"

10. विद्वान राज्य के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि न्यायालय संज्ञान लेते समय आरोप पत्र में उल्लिखित किसी भी धारा को जोड़ या घटा नहीं सकती है, बाहर नहीं कर सकती है या शामिल नहीं कर सकती है क्योंकि आरोप तय करने के समय इसकी अनुमति है।

11. विद्वान राज्य अधिवक्ता अंत में कहते हैं कि धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता (संबंधित धारा 250 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के मददेनजर, आरोपी को आरोप तय करने के चरण में सुनवाई का अवसर दिया जा सकता है। तैयार संदर्भ के लिए धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता (संबंधित धारा 250 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

"धारा 227. उन्मोचन - यदि, वाद के अभिलेख और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर

विचार करने के बाद, और इस संबंध में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की प्रस्तुतियों को

सुनने के बाद, न्यायाधीश मानता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को आरोपमुक्त कर देगा और ऐसा करने के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगा।"

12. मैंने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत की गई पूरी प्रस्तुतियों को देखा है और अभिलेख को ध्यान से अवलोकन किया है।

13. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात राज्य बनाम अफरोज मोहम्मद हसनफट्टा (2019) 20 उच्चतम न्यायालय के वाद 539 के वाद में एक निर्णय पारित किया है; जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि समन के समय, समन आदेश में कारणों को दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, उपरोक्त निर्णय की पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदीप एस. वोडेयार बनाम कर्नाटक राज्य, (2021) 19 उच्चतम न्यायालय के वाद 62 में पारित अपने फैसले के पैराग्राफ 91 में की गई है। प्रदीप एस. वोडेयार (उपरोक्त) में पारित प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 91 को सुविधा के लिए नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

"91. पेप्सी फूड्स लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय को इस आधार पर अलग करते हुए कि यह एक शिकायत वाद में संज्ञान लेने से संबंधित है, न्यायालय ने माना कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान के एक वाद में, मजिस्ट्रेट को सामग्री का अवलोकन करने का लाभ है, इसलिए उसे कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है: गुजरात राज्य बनाम अफरोज मोहम्मद हसनफट्टा (2019) 20 एससीसी 539: (2020) 3 एससीसी (आपराधिक) 876-2

23. जहां तक पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने का संबंध है, मजिस्ट्रेट को जांच के दौरान पुलिस द्वारा एकत्र किए गए आरोप-पत्र, गवाहों के बयान और अन्य सबूतों का लाभ मिलता है। जांच अधिकारी/एसएचओ आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुपालन में और जांच के नियमों के अनुसार की गई जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य एकत्र करता है। इस प्रकार एकत्र किए गए साक्ष्यों और सामग्रियों को जांच अधिकारी के स्तर पर छाना जाता है और उसके बाद आरोप पत्र दायर किया जाता है। उपयुक्त प्रकरणों में, आरोप पत्र दाखिल करने से पहले लोक अभियोजक की राय भी ली जाती है। इस प्रकार न्यायालय को पुलिस द्वारा उसके सामने रखी गई सामग्री के साथ-साथ पुलिस रिपोर्ट का लाभ मिलता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(बी) के तहत, जहां मजिस्ट्रेट ने



पुलिस रिपोर्ट पर किसी अपराध का संज्ञान लिया है और मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है, मजिस्ट्रेट प्रक्रिया जारी करने का निर्देश देता है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान लेने के वाद में, मजिस्ट्रेट को प्रक्रिया जारी करने के लिए कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित प्रकरणों में, मजिस्ट्रेट को केवल आरोपी को समन जारी करने का आदेश पारित करना आवश्यक है। आरोपी को समन जारी करने का ऐसा आदेश पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों पर विचार करते हुए मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर आधारित है और खुद को संतुष्ट करता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर एक वाद में, आरोपी को समन जारी करने के चरण में, मजिस्ट्रेट को कोई कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आरोप पत्र कानून द्वारा वर्जित है या जहां अधिकार क्षेत्र की कमी है या जब आरोप पत्र खारिज कर दिया जाता है या फाइल पर नहीं लिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को आरोप पत्र की अस्वीकृति और इसे फाइल पर न लेने के लिए अपने कारणों को दर्ज करना आवश्यक है।

14. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को आक्षेपित संज्ञान-सह-समन आदेश में कोई अवैधता या कमजोरी नहीं मिलती है, ताकि इस स्तर पर आवेदक को कोई राहत मिल सके। इसके अलावा, यह न्यायालय धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए तथ्य के विवादित प्रश्नों पर निर्णय नहीं दे सकता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में बार-बार उद्धरित किया गया है।

15. तदनुसार, आवेदन **निरस्त** किया जाता है।

16. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त-आवेदक को धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता (संबंधित धारा 250 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत आरोप तय करने के चरण में सुनवाई का अवसर मिलेगा। आवेदक उन्मोचन आवेदन दाखिल करके विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप तय करने के चरण में अपनी सभी शिकायतें उठा सकता है। यदि आवेदक द्वारा ऐसा आवेदन दायर किया जाता है, तो विचारण न्यायालय विवेचना अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सभी सामग्रियों का मूल्यांकन करेगा और उसके बाद उन्मोचन आवेदन पर एक आदेश पारित करेगा।



(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी)

18 अगस्त, 2026

मनीष हिमवान

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।